LOK SABHA

Thursday, *June* 8, 1967/*Jyaistha* 18, 1889 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Fertiliser from Japan

+

*361. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Ramachandra Veerappa:
Shri Ebrahim Sulaiman Sait:
Shri M. Rampure:
Shri N. K. Sanghi:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Y. A. Prasad:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether an Indo-Japanese contract has been signed recently for the purchase of fertilizers from Japan; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). Yes, Sir. A statement showing details of the contracts is placed on the Table of the House.

Statement

Type of Fertiliser	Quantity M. tons.	Delivery Schedule	Price per M. Ton Net.
	(a) *Against Yen Credit*		
Urea	203,498	May/Nov., 1967	$84.63 C & F
Ammonium Sulphate . .	[20,000	May/June, 1967]	$45.69 C & F
Ammonium Chloride . .	40,000	May/Nov., 1967	$46.79 C & F
	(b) *Against Free Foreign Exchange*		
Ammonium Chloride . .	10,000	Nov./Dec., 1967	$40.00 FOB (Jute Packing) *OR* $37.00 FOB. (Paper Packing) At Purchaser's option).

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार महसूस करती है कि हमने जो यह खाद मंगाई है इससे हमारे देश की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी? यदि नहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि बाहर से इन खादों का मंगाना आप कब तक कम करने वाले हैं और कब तक हमारे ही देश में इनका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने लग जाएगा, कब तक हम इस स्थिति में हो जाएंगे कि हम खाद के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें ?

श्री इकबाल सिंह : हिन्दुस्तान में फर्टिलाइजर की पैदावार कम है, इस वास्ते बाहर से मंगाने की जरूरत महसूस होती है और काफी ज्यादा मंगाने की जरूरत महसूस होती है । इस सिलसिले में जापान ने कुछ येन क्रेडिट गवर्नमेंट आफ इंडिया को आफर किया था और उसके मुताबिक बहुत से कांट्रेक्ट्स के तहत यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड मंगाने की बात है । कुछ फ्री फारेन एक्सचेंज में था और उस सिलसिले में भी मंगाया गया है । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कितनी देर मंगाना पड़ेगा, कितनी देर जरूरत पड़ेगी इसका जवाब अगर माननीय सदस्य दूसरी मिनिस्टरी से पूछें तो बेहतर होगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जो उर्वरक जापान से मंगाये जा रहे हैं इनके बारे में जापान सरकार ने क्या कोई शर्तें रखी है, यदि रखी है तो वे शर्तें क्या हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किन दामों पर इनको मंगाया गया है और किन दामों पर इनको यहां बेचा जा रहा है ?

श्री इकबाल सिंह : जापान ने कुछ कर्जा हिन्दुस्तान को दिया था और उसके मुताबिक इन फर्टिलाइजर्स को मंगाया जा रहा है । किन दामों पर मंगाया जा रहा है वह स्टेटमेंट में दिया हुआ है । माननीय सदस्य इसको स्टेटमेंट में देख सकते हैं ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : अन्नोत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है । किन्तु यदि पानी का प्रबन्ध ठीक न हो तो केवल रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण भूमि बंजर हो जाती है । पिछले साल एक एग्रिकल्चरल डेलीगेशन आनसन साहब को मिला था और उसने इंडिस्क्रिमिनेट यूज आफ फर्टिलाइजर पर लीगल बैन लगाने की मांग की थी, क्या यह सत्य नहीं है ? यदि यह सत्य है तो मंत्री महोदय मुझे यह बता दें कि पिछले दस सालों के अन्दर जो उत्पादन यहां बढ़ा है वह ज्यादा भूमि जोत के नीचे आने के कारण बढ़ा है या फर्टिलाइजर के प्रयोग के कारण बढ़ा है ? इसके कुछ आंकड़े मंत्री महोदय दे सकें तो अच्छा होगा ।

श्री इकबाल सिंह : इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हिन्दुस्तान में अनाज की और खाद की भी बहुत कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए चाहे खुराक और चाहे खाद बाहर से मंगानी पड़ती है । जितना खुराक मंगाने में पैसा लगता है उससे कम फर्टिलाइजर पर पैसा लगता है । खाद के प्रयोग से पैदावार भी ज्यादा होती है। लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, जापान ने कर्जा दिया था और उसके मुताबिक यह खाद मंगाया जा रहा है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : किस दाम पर इस उर्वरक को किसानों को दिया जाता है इसका जवाब नहीं आया है । किन दामों पर मंगाया जा रहा है यह तो विवरण में दिया हुआ है लेकिन किन दामों पर इस खाद को यहां दिया जाता है, इसका जवाब नहीं आया है ।

Mr. Speaker: His questions are over.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उसमें यह बताया गया है कि जापान से यूरिया, अमोनियम सलफेट, अमोनियम क्लोराइड मंगाये जा रहे हैं । कीमतें भी बताई गई हैं जिन पर मंगाये गये हैं । दूसरे देशों से भी हम लोग

इन उर्वरकों को मंगाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिन कीमतों पर हम अन्य देशों से इनको मंगाते हैं, उनके मुकाबले में हमको आपात को क्या कीमत देनी पड़ रही है ?

श्री इकबाल सिंह : कितनी देर में आपने मंगाया है, किस किस्म का उसका पैकिंग होना चाहिये और कब वह आए, इस पर बहुत सी बातें मुनहसर करती हैं। जो हमें फो फारेन एक्सचेंज मिला उसके अगेन्स्ट हमने ग्लोबल टेंडर मंगाये और जो हमको कम लगा उसको हमने इसको दिया। जहां तक जापान से मंगाने का ताल्लुक है, चूंकि उन्होंने कर्जा दिया था, उनकी कीमतों को देख कर जो हम बाकी दुनिया के मुकाबले में मुनासिब लगी, फर्टिलाइजर खरीदने का हमने फैसला किया।

Shri Ranga: Is it for a three or four year period that we have reached this agreement, and is the price we are going to pay lower than the price we are obliged to pay to the western countries?

Shri Iqbal Singh: The agreement was reached in May this year and the delivery schedules are May/November, 1967, May/June, 1967, May/November, 1967, November/December, 1967. The dates are mentioned in the statement.

Shri Ranga: Are the prices at which we have contracted with these people for their supplies lower than the prices we are obliged to pay to the western nations from which we are importing?

Shri Iqbal Singh: Of these supplies, one was through global tender; the cheapest tender which we have received we have accepted, that was for 10,000 tonnes of ammonium chloride; for others, some aid and some loans were offered under the yen credit by the Japanese.

Shri Ranga: Yo do not give information at all. Suppose you offer to take at 400 and the other people have been selling at 450, you can say you are gettinngit cheaper. You do not give any straight answer at all.

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jaganath Rao): These purchases are made from the yen credit available to the country as free foreign exchange is not available. Therefore when we purchase from Japan, we have to negotiate with them, and we feel we have obtained the most favourable price.

Shri P. Venkatasubbaiah: Regrading our agreement with Japan under the yen credit, may I know whether Government have explored the possibility of entering into a barter agreement since we are exporting large quantities of iron ore from our country, whether this aspect of the matter has been looked into, and if so, what was the result?

Shri Iqbal Singh: It was immediately required for this year, and these purchases were made from the yen credit for this year. The barter agreement is for the Commerce Ministry. Because we required immediately for this year we have purchased.

श्री क० कु० नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस दाम से हमको यह मिला है उससे कितने फीसदी दाम बढ़ा कर हम यहां पर इसे फार्मर्ज को दे रहे हैं?

Shri Iqbal Singh: This fertiliser will be put in the fertiliser pool, and then it will be sold, and this question had better be asked from the Agriculture Ministry. We have purchased from Japan and it will go to the fertiliser pool, and they will settle the price, at what price it will be sold.

Shri Sradhakar Supakar: May I know why there is such a large difference in the prices. Ammonium chloride obtained for free foreign exchange is 40 dollars, while it costs 46.79 dollars when obtained

against yen credit. May I also know how these prices compare with the price of fertiliser produced in India from Sindri and other places?

Shri Iqbal Singh: This comparison is not relevant, because there is bound to be difference.

Shri Ranga: How much is it, he asks.

Shri Iqbal Singh: It is given in the statement. There is bound to be difference because when somebody goes with cash and wants to purchase, certainly he will purchase cheaper than one who has to take a loan.

Shri P. Venkatasubbaiah: On a point of order. Here the hon. Minister says this is limited in scope so far as his ministry is concerned to getting the fertiliser from Japan and giving it to the Fertiliser Minister. In that case, will it not be desirable that it should be clubbed on to the Minister of Fertilisers because all these questions arise in the course of supplementaries, and members will be naturally inclined to compare the price available in our country with prices elsewhere?

Mr. Speaker: That is a different question. This is on the imports of fertilisers. This ministry imports. If you want to compare prices, you must address the other ministry.

Shri P. Venkatasubbaiah: But there must be scope for members to put question. In that case, it could have been passed on as a written answer.

Shri P. Gopalan: May I know whether it is a fact that the coal-based fertiliser plant proposed to be set up at Korba has been given up: if so, what are the reasons for giving up this plant? Is it a fact that it was due to the pressure exerted by the World Bank that this was given up by the Government?

Shri Iqbal Singh: It relates to the setting up of a plant and this question may be put to my hon. friend the Minister of Petroleum and Chemicals. We do not deal with the setting up of these plants.

Shrimati Lakshmikanthamma: Do the Government propose to import more fertilisers from Japan and is Japan in a position to supply us more fertilisers? In the place of foodgrains, are we preparing to import more and more fertilisers from other countries?

Shri Iqbal Singh: Japan is in a position to supply us more fertilisers but we have to see our own capacity to find the foreign exchange resources, how much money we can spare and so on.

श्री ओ० प्र० त्यागी : माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि हमारे देश में कम्पोस्ट खाद गोबर के रूप में बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है, जो कि फ्युएल के रूप में इस्तेमाल हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी उस की रक्षा कर के विदेशी मुद्रा बचाने का उपाय सोचा है।

Shri Iqbal Singh: This question may better be asked of the Agriculture Ministry.

Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Legislatures

+

***342. Shri P. K. Deo:**
Shri K. P. Singh Deo:
Shri D. N. Deb:

Will the Minister of Social Welfare be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to extend the period of reservation of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes so far as their representation in the State and Central legislatures is concerned; and

(b) if so, the details thereof?